PRGI No. UPHIN/25/A1697

# गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM LUCKNOW

वर्ष : 02
अंक : 058
दि. 27.06.2026,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा


# ऐतिहासिक और बेहद अहम बदलाव : अब कनाडा ने कबूली सच्चाई, क्रैश में था खालिस्तानियों का हाथ

(जीएनएस)।

भारत और कनाडा के रिश्तों में पिछले कई दशकों से खालिस्तानी चरमपंथ एक बड़ा विवाद रहा है। अब इस मुद्दे पर एक ऐतिहासिक और बेहद अहम बदलाव देखने को मिला है। कनाडा की खुफिया एजेंसी कनाडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस (उरक्र) ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया है कि साल 1985 में एयर इंडिया के 'कनिष्क' विमान में हुए बम धमाके के पीछे कनाडा में सक्रिय खालिस्तानी आतंकवादी ही जिम्मेदार थे।

इस आधिकारिक स्वीकार्यता को भारत की बड़ी कूटनीतिक और रणनीतिक जीत माना जा रहा है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां कई सालों से कनाडा सरकार को चेतावनी देती रही थीं कि उसकी जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए हो रहा है। हालांकि, अब तक कनाडा इस सच्चाई को खुलकर स्वीकार करने से बचता रहा था।

**23 जून 1985 का वह दर्दनाक दिन**

एयर इंडिया फ्लाइट 182 पर हुआ हमला दुनिया के सबसे भयानक विमानन आतंकवादी हमलों में से एक माना जाता है। 23 जून 1985 को टोरंटो से उड़ान भरने वाला यह विमान लंदन के रास्ते भारत आ रहा था। लेकिन आयरलैंड के तट के पास उड़ान के दौरान विमान में जोरदार धमाका हुआ और वह समुद्र में गिर गया। इस हादसे में विमान में सवार सभी 329 लोगों की मौत हो गई। यह घटना आज भी वैश्विक विमानन इतिहास के सबसे दर्दनाक आतंकी हमलों में गिनी जाती है।

**CSIS ने पहली बार सार्वजनिक रूप से क्या कहा?**

इस भयावह हादसे की 41वीं बरसी पर कनाडा की खुफिया एजेंसी CSIS ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी अपने आधिकारिक बयान में साफ लिखा कि 23 जून 1985 को कनाडा में मौजूद खालिस्तानी चरमपंथियों द्वारा विमान में रखा गया बम ही इस त्रासदी की वजह बना, जिसमें विमान में सवार सभी यात्रियों की जान चली गई। एजेंसी ने यह भी माना कि यह कनाडा के इतिहास का सबसे घातक आतंकवादी हमला था। उरक्र ने कहा कि इस घटना ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। उस समय यह एजेंसी सिर्फ एक साल पुरानी थी और कनिष्क हादसे ने इसके आगे के विकास और कामकाज की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभाई।

**प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी दी श्रद्धांजलि**

इस मौके पर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी एयर इंडिया फ्लाइट 182 हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने देशवासियों से हिंसक चरमपंथ के खिलाफ एकजुट रहने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि एयर इंडिया फ्लाइट 182 की त्रासदी हमें हमेशा सतर्क रहने और अपनी सुरक्षा एजेंसियों को और मजबूत बनाने की सीख देती है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।

**भारत के पुराने आरोपों को मिली बड़ी ताकत**

कनाडा का यह नया रुख भारत की उस बात को मजबूत करता है जिसे नई दिल्ली कई सालों से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाती रही है। भारत लगातार कहता रहा है कि कनाडा ने राजनीतिक कारणों से ऐसे चरमपंथी तत्वों को पनाह दी, जो वहां बैठकर भारत की सुरक्षा, एकता और अखंडता के खिलाफ गतिविधियां चलाते रहे। अब जब कनाडा की अपनी खुफिया एजेंसी ने सार्वजनिक रूप से खालिस्तानी आतंकवादियों की भूमिका स्वीकार कर ली है, तो भारत के लंबे समय से उठाए जा रहे दावों को भी नई मजबूती मिली है।

329 लोगों की ने गवाई थी जान

इस आतंकी हमले में जान गंवाने वाले 329 लोगों में से 268 कनाडाई नागरिक थे, जो भारतीय मूल के थे। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि विमान में सवार लोगों में लगभग एक-तिहाई छोटे बच्चे थे। स्कूलों की छुट्टियां होने के कारण वे अपने परिवारों के साथ भारत घूमने आ रहे थे। जांच में सामने आया कि आतंकियों ने एक अनक्लेम्ड बैग में बम छिपाकर उसे विमान तक पहुंचाया था, जिसके बाद उड़ान के दौरान धमाका हुआ।

**जांच में सामने आई कनाडा की बड़ी लापरवाही**

इस मामले की जांच के दौरान कनाडा की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को भारी आलोचना झेलनी पड़ी। बाद में हुई न्यायिक जांचों में सामने आया कि कनाडाई पुलिस और खुफिया एजेंसियों के बीच सही तालमेल नहीं था। इसी वजह से इतनी बड़ी साजिश का समय रहते पता नहीं चल सका और सैकड़ों लोगों की जान चली गई। इस मामले को कनाडा की सबसे बड़ी सुरक्षा विफलताओं में भी गिना जाता है।

**2025 की रिपोर्ट से ही मिलने लगे थे बदलाव के संकेत**

मार्च 2025 में जारी अपनी सार्वजनिक रिपोर्ट में भी उरक्र ने पहली बार कनाडा में सक्रिय खालिस्तानी संगठनों को देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया था। अब एयर इंडिया कनिष्क ब्लास्ट को लेकर आया कनाडा का ये नया बयान दिखाता है कि आतंकवाद के मुद्दे पर कनाडा की सोच और नीतियों में बड़ा बदलाव आ रहा है। वहीं, विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कनाडा आतंकवाद और चरमपंथ के खिलाफ इसी तरह सख्त रुख अपनाता है, तो भारत के साथ उसके आर्थिक, व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों को भी नई दिशा मिल सकती है।

# 'मैंने कहा था- कार्रवाई होगी और कार्रवाई शुरू हो गई', राम मंदिर मामले में बोले सीएम योगी, कांग्रेस पर जमकर बरसे

**यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से राम मंदिर केस में एसआईटी जांच पर उठाए गए सवालों का जवाब दिया। उन्होंने देवरिया में एक जनसभा में कांग्रेस को भी निशाना बनाया।**

(जीएनएस)।

देवरियाः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाया है। अयोध्या के दौरे पर आए अरविंद केजरीवल ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी की जांच करने वाली एसआईटी पर सवाल उठाए हैं। सीएम योगी ने कहा है कि, जब इन्हें कुछ नहीं मिला तो रामभक्तों पर आक्षेप कर रहे हैं,अयोध्या धाम को बदनाम कर रहे हैं। सीएम योगी ने देवरिया में एक जनसभा में यह बात कही।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि, 'एक दिल्ली से सज्जन वहां आए हैं, अयोध्या। दिल्ली की जनता ने उन्हें 15 वर्ष अवसर दिया,लेकिन दिल्ली को उन्होंने बबार्दी,भ्रष्टाचार के सिवा कुछ



नहीं दिया, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, डबल इंजन की सरकार ने 9 वर्ष में अयोध्या को जो सवांरा है, देखें इस मॉडल को। फिर अपने कारनामों पर पश्चाताप करो। यह न्याय अयोध्या के साथ जो डबल इंजन की सरकार ने किया, अगर यही न्याय आम आदमी पार्टी दिल्ली के साथ करती तो दिल्ली भी चमकती, जैसे आज अयोध्या चमक रही है।'

सीएम योगी ने कहा कि, मैंने 19 जून को अयोध्या के दौरे पर कहा था, जन आस्था के साथ खिलवाड़ न हो। अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो, श्रीराम की मयार्दा का पालन करना सीखो। मैंने कहा था कि एसआईटी की रिपोर्ट आने पर कार्रवाई होगी। एसआइटी रिपोर्ट आई, कार्रवाई प्रारंभ हो गई है।

उन्होंने कहा कि, जन आस्था के साथ जो खिलवाड़ करेगा, उसके साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेंगे। आज मोहर्रम है, कहीं किसी का अता पता नहीं है, कोई शस्त्र नहीं निकल रहा, उत्सव के माहौल में कोई उपद्रव नहीं कर सकता, अगर करेगा तो सात पीढ़ियों तक भुगतेगा।

योगी ने कहा कि, जो लोग आज आक्षेप कर रहे हैं, इनकी मंशा अच्छी नहीं है। ये वे लोग हैं जो लोग भगवान राम को नकार चुके थे, कहते थे कि राम हुए ही नहीं। ये लोग अयोध्या को नकारते रहे। दूसरा पक्ष वह है जो जय श्रीराम पर लाठी गोली चलाते थे, तुम बताओगे हमें आस्था। रामनवमी पर दंगा करवाते थे, कावड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगाते थे। कांग्रेस ने देश को लूटा ही नहीं था, बल्कि नोचा था। सरकार ने पहले दिन कहा था कि दूध का दूध पानी का पानी होगा।

मैं फिर कहता हूं कि रामभक्तों की अग्निपरीक्षा मत लो, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ मत करो, प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत पेश करो।

# पीएम मोदी ने की ब्रह्माकुमारीज के 'नशामुक्त भारत अभियान' की सराहना, 3 साल में 3.54 करोड़ लोगों ने लिया संकल्प

**राजस्थान में आबूरोड के ब्रह्माकुमारीज संस्थान के 'नशामुक्त भारत अभियान' की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहना करते हुए इसे युवाओं के लिए सराहनीय पहल बताया। भारत सरकार के सहयोग से तीन साल में देशभर में 27,640 कार्यक्रम और 50 हजार पाठशालाओं में जागरूकता अभियान चलाए गए है।**

(जीएनएस)।

सिरोहीः आबूरोड के ब्रह्माकुमारीज संस्थान के मेडिकल विंग द्वारा चलाए जा रहे नशामुक्त भारत अभियान की सफलता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभियान की सराहना करते हुए शुभकामना संदेश भेजा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रह्माकुमारीज द्वारा नशामुक्त भारत के समर्थन में चलाया जा रहा राष्ट्रव्यापी जनआंदोलन युवाओं को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करने वाली सराहनीय पहल है।

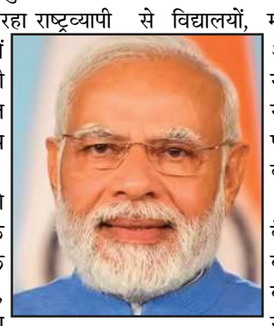



प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में कहा कि नशे की गिरफ्त से मुक्त युवा अपनी ऊर्जा, प्रतिभा और क्षमता का उपयोग राष्ट्र निर्माण में कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखना केवल सामाजिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय कर्तव्य भी है। उन्होंने ब्रह्माकुमारीज द्वारा आध्यात्मिक जागरूकता, मूल्य आधारित शिक्षा, राजयोग ध्यान और जन-जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यालयों, महाविद्यालयों, गांवों और विभिन्न समुदायों तक नशामुक्ति का संदेश पहुंचाने के प्रयासों की सराहना की।

मेडिकल विंग के सचिव डॉ. बनारसी लाल ने बताया कि भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सहयोग से चलाए जा रहे अभियान के तहत तीन साल में देशभर में 27,640 कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों के माध्यम से 3.54 करोड़ लोगों को नशामुक्ति का संकल्प दिलाया गया।

50 हजार पाठशालाओं में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

अभियान में दो लाख से अधिक वालेंटियर भाई-बहनों और करीब दो हजार डॉक्टरों व नर्सों ने निःशुल्क सेवाएं दीं। वहीं 50 हजार पाठशालाओं में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। मेडिकल विंग पिछले 45 वर्षों से नशामुक्त समाज और स्वस्थ भारत के संकल्प के साथ कार्य कर रहा है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि नशामुक्त भारत अभियान अब जन अभियान बन चुका है और ब्रह्माकुमारीज के सहयोग से इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।

# चंदा चोरी में एफआईआर दिखावा, बड़े लोगों को बचाने की कोशिश : केजरीवाल

**अरविंद केजरीवाल अयोध्या के दौरे पर हैं, उन्होंने राम मंदिर में दर्शन किए और बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला, केजरीवाल ने आरोप लगाया कि इतना बड़ा घोटाला आखिर कैसे छोटे कर्मचारी कर सकते हैं.**

(जीएनएस)।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन-पूजन किए. दर्शन के बाद मीडिया से बात करते हुए केजरीवाल ने मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में दर्ज की गई FIR महज एक दिखावा और छलावा है.

अरविंद केजरीवाल ने घोटाले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा, "इतने बड़े घोटाले को इतने लंबे समय तक केवल जूनियर स्तर के कर्मचारी अकेले अंजाम नहीं दे सकते थे. यह पूरी तरह से साफ है कि इस भ्रष्टाचार की कड़ियां और तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं. इस मामले में असली प्रभावशाली लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, जबकि पूरा दोष निचले स्तर के कर्मचारियों के सिर मढ़ा जा रहा है."

भगवान राम के दरबार में न्याय की गुहार लगाने की बात कहते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा, "हमने भगवान राम के दर्शन किए और मंदिर में हुए इस इतने बड़े घोटाले को लेकर प्रभु से प्रार्थना की है, जिन्होंने भी यह पाप किया है और आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, उन्हें भगवान राम कठोर से कठोर सजा दें."

केजरीवाल के साथ आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी मौजूद थे, बता दें कि एक दिन पहले ही संजय सिंह लखनऊ पहुंचे थे, उन्होंने आरोप लगाया है कि ट्रस्ट ने जमीनों की खरीद में भी भेदभाव किया है. उनका कहना है कि राम मंदिर के पास की जमीने सस्ते दामों में खरीदा गया और जो जमीनें दूर थीं उन्हें महंगे दामों पर खरीदा गया. उनका आरोप है कि ट्रस्ट के करीबियों को फायदा पहुंचाया गया है.

केजरीवाल राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी के मामले में लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं, उन्होंने एक दिन पहले ही एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा- 'चंपत राय ने PM को हिसाब देने से मना कर दिया. इतनी हिम्मत कैसे हो गई चंपत राय की. ऐसे क्या राज जानते हैं चंपत राय कि PM भी उनके सामने मजबूर हैं?

और दूसरी ओर SIT छोटे छोटे कर्मचारियों को बुला कर सबकी आंखों में धूल झोंक रही है.

## प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड की क्वीन मैक्सिमा से मुलाकात की

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार, नीदरलैंड की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मुलाकात के दौरान, उन्होंने इस बात की चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बना कर जीवन की सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है।

# फोर्टिस अस्पताल पर सीएम रेखा गुप्ता का एक्शन, मरीज की मौत जांच रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे, क्या है पूरा मामला?

(जीएनएस)।

दिल्ली के शालीमार बाग स्थित फोर्टिस अस्पताल अब सरकार की जांच के दायरे में है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर बनाई गई जिला स्तरीय जांच समिति की शुरूआती रिपोर्ट में कई ऐसी खामियां सामने आई हैं, जिनके बाद सरकार ने अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। मामला सिर्फ इलाज में कथित लापरवाही तक सीमित नहीं है, बल्कि भवन नियमों, फायर सेफ्टी और अस्पताल के संचालन से जुड़े कई पहलुओं की भी जांच की जा रही है।



इस पूरे मामले की शुरूआत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की जनसुनवाई के दौरान मिली एक शिकायत से हुई। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि चाकू के हमले में घायल उनके बेटे को इलाज के लिए फोर्टिस अस्पताल लाया गया था, लेकिन इलाज शुरू करने से पहले पैसे मांगे गए। परिवार का दावा है कि समय पर इलाज नहीं मिलने की वजह से युवक की मौत हो गई। शिकायत को गंभीर मानते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तत्काल जांच के आदेश दिए।

सीएम रेखा गुप्ता के निर्देश के बाद केंद्रीय जिला मजिस्ट्रेट एस. एस. परिहार की अगुवाई में स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, दिल्ली फायर सर्विस और दूसरे विभागों की संयुक्त टीम ने अस्पताल का निरीक्षण किया। जांच के दौरान आपातकालीन वार्ड के रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज भी देखे गए।

जिला मजिस्ट्रेट एस. एस. परिहार ने बताया कि पिछले कई महीनों से अस्पताल को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं। जनसुनवाई के दौरान भी लोगों ने कई बार अनियमितताओं की बात उठाई थी। उन्होंने कहा कि शुरूआती जांच में कुछ जगहों पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (रडढ) और तय गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन नहीं मिलने के संकेत मिले हैं। विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

# चीन को चिकन नेक पर लाया बांग्लादेश, तीस्ता नदी पर कर ली बड़ी डील! भारत की बढेगी टेंशन?

(जीएनएस)।

भारत और बांग्लादेश के बीच कई सालों से तीस्ता नदी के पानी को लेकर विवाद चल रहा है। लेकिन अब यह मामला सिर्फ पानी तक सीमित नहीं है। बांग्लादेश ने तीस्ता नदी प्रोजेक्ट में चीन को शामिल करने का फैसला लिया है। इसके बाद यह विवाद अब सुरक्षा और रणनीति से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन गया है। बांग्लादेश का कहना है कि यह प्रोजेक्ट खेती, सिंचाई और बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए जरूरी है। वहीं भारत को डर है कि इस बहाने चीन उसकी सीमा के बेहद करीब अपनी मौजूदगी बढ़ा सकता है।

क्या है तीस्ता नदी प्रोजेक्ट?

बांग्लादेश में तीस्ता नदी में पानी की कमी, ज्यादा गाद और हर साल आने वाली बाढ़ बड़ी समस्या है। इन्हें दूर करने के लिए उसने करीब 98 करोड़ डॉलर की लागत वाली तीस्ता रिवर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट (ळफ्ऌटफ्ढ) बनाई है। इस प्रोजेक्ट के लिए बांग्लादेश ने चीन से करीब 72.5 करोड़ डॉलर की आर्थिक मदद मांगी। साल 2016 में दोनों देशों के बीच इस पर शुरूआती सहमति भी बन गई थी। बाद में चीन ने इसे अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (इफ्क्र) से जोड़ने की कोशिश की, जिससे भारत की चिंता और बढ़ गई।

मार्च 2025 में बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस चीन गए थे। इस दौरान जारी साझा बयान में बांग्लादेश ने पहली बार खुलकर कहा कि वह इस प्रोजेक्ट में चीनी तकनीक और निवेश का स्वागत करता है। इससे साफ हो गया कि चीन अब इस प्रोजेक्ट में बड़ी भूमिका निभाने वाला है।

भारत की सबसे बड़ी चिंता इस प्रोजेक्ट की लोकेशन है। यह प्रोजेक्ट सिलीगुड़ी कॉरिडोर से 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। इस इलाके को 'चिकन नेक' कहा जाता है। यह भारत का बहुत अहम इलाका है क्योंकि यही रास्ता देश के पूर्वोत्तर राज्यों को बाकी भारत से जोड़ता है। अगर इस इलाके के पास चीन लंबे समय तक काम करता है, तो भारत को सुरक्षा का खतरा महसूस होता है।

भारत को किस बात का डर है?

भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि विकास प्रोजेक्ट के नाम पर चीन इस इलाके की जानकारी जुटा सकता है या निगरानी कर सकता है। इसी वजह से भारत पहले भी बांग्लादेश से इस प्रोजेक्ट में चीनी कंपनियों को शामिल नहीं करने की अपील कर चुका है। भारत के लिए यह सिर्फ नदी या पानी का मामला नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी सवाल है।

# सम्पादकीय

## यूपी बीजेपी में संगठनात्मक फेरबदल

उत्तर प्रदेश भाजपा की नई टीम में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश साफ दिख रही है। पार्टी ने जिस तरह ब्रा१ाण, पिछड़ा, दलित और अलग-अलग इलाकों से जुड़े चेहरों को जगह दी है, उससे यह संदेश दिया जा रहा है कि संगठन केवल एक वर्ग या एक क्षेत्र के सहारे नहीं चलेगा, बल्कि हर बड़े सामाजिक समूह को साथ लेकर आगे बढ़ने की रणनीति बनाई जा रही है। पार्टी के भीतर यह चर्चा भी तेज है कि नई टीम के गठन में प्रदेश अध्यक्ष से ज्यादा राष्ट्रीय नेतृत्व के भरोसेमंद रणनीतिकार सुनील बंसल की छाप नजर आती है। यही वजह है कि इसे सिर्प संगठनात्मक पेरबदल नहीं, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार करने की कवायद भी माना जा रहा है। भाजपा जानती है कि उत्तर प्रदेश में जीत सिर्प नारे से नहीं, बल्कि जातीय समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन और बूथ स्तर की पकड़ से तय होती है। जनसाधारण के नजरिये से देखें तो पार्टी ने ब्राह्मणों की नाराजगी को भी गंभीरता से लेने की कोशिश की है। नई टीम में इस वर्ग को अपेक्षावृत अच्छी जगह देकर भाजपा यह संदेश देना चाहती है कि वह किसी एक सामाजिक आधार को कमजोर नहीं होने देगी। इससे यह भी माना जा रहा है कि पार्टी पुराने भरोसेमंद मतदाताओं को फिर से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है, क्योंकि चुनाव के समय संगठन का यह संतुलन बहुत मायने रखता है।सूत्रों और राजनीतिक चचाओं में यह बात भी उठ रही है कि सुनील बंसल की भूमिका अब भी उतनी ही अहम है, जितनी पहले थी। वे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक नब्ज को गहराई से समझते हैं और 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने में उनकी रणनीति की बड़ी भूमिका मानी गई थी। इसीलिए नई टीम को देखकर बहुत से लोग इसे उसी पुराने संगठनात्मक मॉडल की वापसी के रूप में देख रहे हैं, जिसमें नीचे तक पकड़, सामाजिक गणित और लगातार संवाद सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इसी संदर्भ में संदीप बंसल का नाम भी चर्चा में आ रहा है। राजनीतिक समझ रखने वाले लोग मान रहे हैं कि आने वाले चुनाव में वे भी प्रदेश की राजनीति में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इसका कारण यह है कि भाजपा अब ऐसे चेहरों को आगे बढ़ाने की तैयारी में दिख रही है जो संगठन, वर्ग- संतुलन और चुनावी प्रबंधन तीनों में काम आ सवें। यदि यह प्रवृत्ति आगे बढ़ी, तो संदीप बंसल जैसे नेताओं की उपयोगिता और बढ़ सकती है।नई टीम की सबसे बड़ी खासियत यही मानी जा रही है कि उसमें केवल चेहरों का नहीं, बल्कि संदेशों का भी संतुलन साधा गया है। एक तरफ पार्टी यह दिखाना चाहती है कि वह सभी बड़े समाजों को साथ लेकर चल रही है, दूसरी तरफ यह भरोसा भी देना चाहती है कि चुनावी प्रबंधन पहले की तरह मजबूत हाथों में है। जनता के बीच भी यही धारणा बनती है कि भाजपा संगठन को हल्के में नहीं लेती और हर बड़े चुनाव से पहले अपनी व्यवस्था को फिर से कसती है। खैर, उत्तर प्रदेश भाजपा की नई टीम में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को खास तौर पर साधने की कोशिश दिखाई दी है। पार्टी ने 19 प्रदेश उपाध्यक्ष, 8 प्रदेश महामंत्री और 19 प्रदेश मंत्रियों के साथ पूरी कार्यर्कारिणी को नए सिरे से सजा दिया है, जिसमें ब्रा१ाण, पिछड़ा, दलित, पूर्वाचल, पमिमी यूपी और अवधकानपुर जैसे क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व ध्यान से रखा गया है। प्रदेश उपाध्यक्षों की सूची में सुरेश राणा, सत्यपाल सैनी, ब्रज बहादुर सिह, डॉ. धर्मेंद्र सिह, मोहित बेनीवाल, देवेश कोरी, प्रियंका रावत, दरुविजय शाक्य, रमेश सिह, नीरज सिह, अर्चना मिश्रा, पूजा पाल, शंकर गिरी, कामेश्वर सिह, डॉ. वृतिका अग्रवाल, सुरेश मौर्य, राजेश यादव, वृष्ण बिहारी राय और आलोक गुप्ता को जिम्मेदारी दी गई है. इनमें सुरेश राणा, सत्यपाल सैनी, ब्रज बहादुर सिह, डॉ. धर्मेंद्र सिह, मोहित बेनीवाल, देवेश कोरी, प्रियंका रावत, दरुविजय शाक्य, रमेश सिह, नीरज सिह, अर्चना मिश्रा, पूजा पाल, शंकर गिरी, कामेश्वर सिह, डॉ. वृतिका अग्रवाल, सुरेश मौर्य, राजेश यादव, वृष्ण बिहारी राय और आलोक गुप्ता जैसे नाम अलग-अलग सामाजिक और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि का संदेश देते हैं. प्रदेश महामंत्रियों में रामप्रताप सिह चौहान, गीता शाक्य, अभिजात मिश्रा, उपेंद्र रावत, संजय राय, शंकर लोधी, दिलीप पटेल और राजेश चौधरी को जगह मिली है।

# केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर पहली बार 28-29 जून को दिल्ली में होगा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन

(जीएनएस)।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 28 और 29 जून को नई दिल्ली के पूसा स्थित भारत रत्न सी. सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे, जहां गांवों के समग्र विकास, प्रमुख योजनाओं की समीक्षा और भविष्य की रणनीति पर व्यापक चर्चा की जाएगी।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप केंद्र सरकार ग्रामीण भारत के तेज, समावेशी और सतत विकास को नई दिशा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा मंथन करने जा रही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में पहली बार व्यापक रूप से आयोजित इस राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन-2026 में केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए गांवों के विकास के लिए साझा रणनीति तैयार की जाएगी।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य 'विकसित ग्राम, विकसित भारत' के विजन को जमीन पर उतारना है। इसके तहत विकसित भारत- जी राम जी (VB-GRAM-G) अधिनियम-2025 के प्रभावी क्रियान्वयन, ग्राम पंचायत स्तर पर योजनाओं की बेहतर योजना-निर्माण प्रक्रिया और संसाधनों के कुशल उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि सम्मेलन में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण , प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना , दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन , ग्रामीण कौशल विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जैसी प्रमुख योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की जाएगी।

**सभी राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्री होंगे शामिल**

इस सम्मेलन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री भाग लेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति-निमार्ताओं और विभिन्न योजनाओं से जुड़े विशेषज्ञों की भी सक्रिय भागीदारी रहेगी। इस राष्ट्रीय मंथन में राज्यों के अनुभव, नवाचार और जमीनी चुनौतियों पर खुलकर चर्चा होगी, जिससे नीतिगत स्तर पर मजबूत और व्यावहारिक समाधान सामने आ सकें।

**थीमैटिक सत्र और बेस्ट प्रैक्टिस पर फोकस**

शिवराज सिंह ने कहा कि सम्मेलन के दौरान विभिन्न थीमैटिक और ब्रेकआउट सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें ग्रामीण आवास, सड़क कनेक्टिविटी, आजीविका, कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। राज्यों द्वारा अपनाई गई सफल पहल और नवाचारों को साझा किया जाएगा, ताकि उन्हें अन्य राज्यों में भी लागू किया जा सके।

केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि 'लखपति दीदी' पहल के तहत स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, ग्रामीण उद्यमिता और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उपायों पर विशेष चर्चा होगी। इसके साथ ही ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास और बाजार से जुड़ाव पर भी फोकस रहेगा।

**तकनीक और अक के उपयोग पर जोर**

श्री चौहान ने बताया कि सम्मेलन में ग्रामीण विकास योजनाओं में तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को विशेष महत्व दिया जाएगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म, रियल टाइम मॉनिटरिंग, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए विभिन्न तकनीकी समाधानों पर चर्चा की जाएगी, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी और प्रभावशीलता लाई जा सके।

**तय होगी आगे की दिशा**

शिवराज सिंह ने बताया कि सम्मेलन के दूसरे दिन 29 जून को प्लेनरी सत्रों और मंत्रिस्तरीय चचाओं के माध्यम से सभी राज्यों के सुझाव लिए जाएंगे और भविष्य की कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह समापन सत्र में सम्मेलन के निष्कर्षों को प्रस्तुत करेंगे और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में गांवों की केंद्रीय भूमिका पर अपनी बात रखेंगे।

**ग्रामीण भारत के लिए नए संकल्प और ठोस कार्ययोजना**

उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन केवल समीक्षा का मंच नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत के लिए नए संकल्प और ठोस कार्ययोजना तय करने का अवसर है, जिससे देश के हर गांव को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके, जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में केंद्र सरकार की प्राथमिकता है।

**महत्वपूर्ण प्रकाशनों का होगा विमोचन**

सम्मेलन के दौरान ग्रामीण विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रकाशनों का विमोचन भी किया जाएगा। इनमें जल सुरक्षा, ग्राम विकास योजना, महिला सशक्तिकरण, आजीविका और सफलता की कहानियों से जुड़े दस्तावेज शामिल होंगे, जो राज्यों और ग्राम पंचायतों के लिए मार्गदर्शक का काम करेंगे।

# 'नए एफसीआरए नियम सिविल सोसायटी पर सुनियोजित हमला': कांग्रेस का पीएम मोदी को खत

(जीएनएस)।

कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन नियम, 2026 विकास और कल्याण कार्य करने वाले NGO और अल्पसंख्यक संस्थानों का गला घोंटने के लिए लाए गए हैं। उन्होंने नये नियम को तुरंत वापस लेने की मांग की है।

कांग्रेस ने विदेशी चंदा नियमन यानी एफसीआरए के नियमों में हाल में किए गए बदलावों को सिविल सोसायटी पर सुनियोजित हमला करार दिया है। इसने कहा है कि यह एनजीओ और अल्पसंख्यक संस्थानों का गला घोंटने की कोशिश है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि नए एफसीआरए नियम को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए।

कांग्रेस का आरोप है कि सरकार इन नियमों के जरिए गैर-सरकारी संगठनों यानी एनजीओ और सामाजिक संस्थाओं की स्वतंत्रता को सीमित करना चाहती है, जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि इन बदलावों का मकसद विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है।

**क्या हैं नए FCRA नियम?**

गृह मंत्रालय ने हाल ही में ऋफ्छ नियमों में संशोधन किया है। नए नियमों के तहत विदेशी फंड पाने वाले संगठनों को अपने काम के उद्देश्य और कार्यक्षेत्र को सरकार द्वारा तय की गई सूची में से चुनना होगा। इसके अलावा किसी संस्था के प्रमुख पदों पर यदि भारतीय मूल के अलावा अन्य विदेशी नागरिक हैं तो सामान्य परिस्थितियों में उसे न तो विदेशी फंड पाने की अनुमति दी जाएगी और न ही पंजीकरण होने दिया जाएगा। सरकार ने कुछ धार्मिक और आस्था आधारित गतिविधियों को अनुमति दी है, लेकिन धर्मांतरण से जुड़ी गतिविधियों को कई श्रेणियों से बाहर रखा गया है।

**कांग्रेस ने क्या आपत्ति जताई?**

प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में वेणुगोपाल ने कहा कि ये नियम किसी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नहीं बल्कि सामाजिक संगठनों को नियंत्रित और कमजोर करने के लिए बनाए गए हैं। उन्होंने लिखा कि सरकार एनजीओ को एक तयशुदा सूची से काम या गतिविधियाँ चुनने और सीमित क्षेत्रों में काम करने के लिए मजबूर कर रही है। इससे संस्थाओं का वह लचीलापन खत्म हो जाएगा, जिसके जरिए वे आपदा, सामाजिक संकट या स्थानीय जरूरतों के अनुसार काम करती हैं।

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि अलग-अलग राज्यों या अतिरिक्त गतिविधियों के लिए अलग शुल्क लगाना सामाजिक कार्य करने वाली संस्थाओं पर 'प्रशासनिक टैक्स' थोपने जैसा है।

**छोटे संगठनों पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर?**

वेणुगोपाल का कहना है कि नए नियमों में छोटी प्रशासनिक गलतियों पर भी भारी जुमार्ने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में जुमार्ना फंड की 30 प्रतिशत राशि या न्यूनतम एक लाख रुपये तक हो सकता है। इससे छोटे और जमीनी स्तर पर काम करने वाले संगठन आर्थिक रूप से बुरी तरह प्रभावित होंगे।

कांग्रेस का दावा है कि बड़ी संस्थाओं के पास कानूनी और प्रशासनिक संसाधन होते हैं, लेकिन गांवों और दूरदराज क्षेत्रों में काम करने वाले छोटे संगठन ऐसे नियमों का सामना नहीं कर पाएंगे।

**सोशल मीडिया की जानकारी क्यों मांगी?**

कांग्रेस ने नियमों में सोशल मीडिया अकाउंट, वेबसाइट और प्रकाशित सामग्री की जानकारी अनिवार्य रूप से देने के प्रावधान पर भी आपत्ति जताई है। वेणुगोपाल ने इसे 'निगरानी की मानसिकता' बताया और कहा कि इससे नागरिक संगठनों की गतिविधियों पर अनावश्यक नियंत्रण बढ़ेगा। उनका आरोप है कि सरकार सामाजिक संगठनों की निगरानी करने और उन्हें दबाव में रखने की कोशिश कर रही है।

**अल्पसंख्यक संस्थाओं को लेकर भी चिंता**

कांग्रेस ने कहा कि नए नियमों का असर विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा संचालित संस्थाओं पर पड़ सकता है। पार्टी का कहना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में काम करने वाली अनेक संस्थाएं पहले से ही ऋफ्छ जुड़े सख्त नियमों का सामना कर रही हैं और नए संशोधन उनके कामकाज को और मुश्किल बना देंगे।

**पहले भी हजारों लाइसेंस रद्द हुए**

पत्र में कांग्रेस नेता ने दावा किया कि पिछले कुछ वर्षों में ऋफ्छ का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया गया है और हजारों संगठनों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। उनके अनुसार, इससे स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका और सामाजिक सहायता से जुड़े कई कार्यक्रम प्रभावित हुए हैं, जिनका लाभ लाखों लोगों को मिलता था। उन्होंने कहा कि एक जीवंत लोकतंत्र में स्वतंत्र और मजबूत सिविल सोसायटी की जरूरत होती है, न कि ऐसी संस्थाओं की जो सरकारी दबाव में काम करें।

कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार पहले संसद में ऋफ्छ संशोधन लाने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन अब उन्हीं बदलावों को नियमों के माध्यम से लागू किया जा रहा है। पार्टी का कहना है कि इससे संसद में व्यापक चर्चा और लोकतांत्रिक बहस की प्रक्रिया कमजोर होती है।

**सरकार की मंशा पर सवाल**

कांग्रेस का आरोप है कि नए नियमों का मकसद सामाजिक संगठनों को आर्थिक और प्रशासनिक रूप से कमजोर करना है। पार्टी ने इन्हें कठोर और दमनकारी कदम बताते हुए तत्काल वापस लेने की मांग की है।

# शोएब अख्तर के भाई के जनाजे में आतंकियों का जमावड़ा, कंधे पर हाथ रखे दिखे दहशतगर्द

(जीएनएस)।

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर के बड़े भाई शाहिद अख्तर के जनाजे को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। जून 2026 के आखिरी हफ्ते में इस्लामाबाद में हुए इस जनाजे में खेल और राजनीति से जुड़े कई बड़े लोग पहुंचे थे। लेकिन विवाद तब शुरू हुआ, जब सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो और तस्वीरों में कुख्यात आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और उससे जुड़े राजनीतिक संगठन पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग (PMML) के दहशतगर्दों को भी वहां मौजूद देखा गया।

**सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से बढ़ा विवाद**

यह मामला तब सामने आया, जब इस्लामाबाद के एच-8 कब्रिस्तान में हुए नमाज-ए-जनाजा के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगे। इन वीडियो में प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े लोग आराम से घूमते और शोएब अख्तर के परिवार के सदस्यों से मिलते-जुलते नजर आए। सबसे हैरानी की बात यह रही कि इन तस्वीरों को छिपाने की कोशिश भी नहीं की गई।

डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक, लश्कर-ए-तैयबा और उसके राजनीतिक दल PMML के आधिकारिक मीडिया विंग ने खुद इन तस्वीरों और वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा किया। वीडियो में PMML के इस्लामाबाद अध्यक्ष इनाम उर रहमान कम्बोह अपने सहयोगियों के साथ दिखाई दिए। उन्हें शोएब अख्तर के परिवार से गले मिलकर सांत्वना देते हुए भी देखा गया। इसके बाद सवाल उठने लगे कि प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े लोगों को एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर के निजी पारिवारिक कार्यक्रम तक इतनी आसानी से पहुंच कैसे मिली।

**लश्कर और PMML के रिश्ते क्यों हैं चर्चा में?**

सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग (PMML) लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में है। कई विशेषज्ञ इसे मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के नेटवर्क से जुड़ा राजनीतिक मंच है। उनका दावा है कि जमात-उद-दावा और लश्कर-ए-तैयबा पर प्रतिबंध लगने के बाद इस नेटवर्क ने राजनीतिक पहचान के साथ काम करना शुरू किया। इनाम उर रहमान कम्बोह को भी इसी संगठन का प्रमुख चेहरा माना जाता है।

**अब तक शोएब अख्तर ने नहीं दी कोई प्रतिक्रिया**

इस पूरे विवाद पर फिलहाल शोएब अख्तर या उनकी टीम की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वहीं, वैश्विक सुरक्षा एजेंसियां इस घटना को प्रतिबंधित संगठनों द्वारा मुख्यधारा के कार्यक्रमों के जरिए खुद को सामान्य और स्वीकार्य दिखाने की कोशिश के रूप में देख रही हैं। आने वाले दिनों में यह मामला पाकिस्तान की राजनीति, सुरक्षा और खेल जगत में चर्चा का बड़ा विषय बना रह सकता है।

# लोकसभा में एनडीए का आंकड़ा 300 पार होते ही इण्डिया गठबंधन में बेचैनी? अब इस पार्टी को मनाने में जुटे विपक्षी

(जीएनएस)।

लोकसभा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की बढ़ती ताकत ने सियासी गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जिस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के पास 293 सीटें थीं, वह अब सहयोगियों की मदद से तेजी से बढ़ते हुए 300 का आंकड़ा पार कर चुका है। एनडीए के इस बढ़ते कुनबे ने विपक्षी खेमे यानी क्ठऊक्रअ गठबंधन की नींद उड़ा दी है।

विपक्षी खेमे में इस वक्त सबसे बड़ी चिंता अपने पुराने और मजबूत साथी द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम (ऊ्टङ) को बचाए रखने की है, जो फिलहाल कुछ नाराज दिखाई दे रहा है। माना जा रहा है कि संसद में बदलते समीकरणों के बीच इंडिया गठबंधन अपने पुराने सहयोगी की नाराजगी दूर करने में जुट गया है।

विपक्षी खेमे में मची इस खलबली के पीछे असली वजह सीटों का गणित है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 20 बागी सांसदों ने एक अलग गुट 'नेशनल सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया' बनाकर ठऊ्र को अपना समर्थन दे दिया, जिससे आंकड़ा सीधे 313 पर पहुंच गया। इसके ठीक बाद उद्धव ठाकरे गुट के 6 और सांसद पाला बदलकर शिंदे गुट के साथ आ गए, जिससे एनडीए की ताकत 319 तक जा पहुंची।



अब अगर लोकसभा में 22 सांसदों वाली ऊ्टङ भी मुद्दों के आधार पर सरकार का साथ देती है, तो यह संख्या 341 हो जाएगी। संसद के निचले सदन में दो तिहाई बहुमत के लिए वैसे तो 362 सीटें चाहिए, लेकिन 3 सीटें खाली होने की वजह से यह जादुई आंकड़ा फिलहाल 360 का है। बजट सत्र में महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर सरकार को 298 सांसदों का साथ मिला था, जो जरूरी आंकड़े से 62 कम था। यही वजह है कि एनडीए अब नए साथियों को जोड़ने में लगा है।

इस पूरे फेरबदल के बीच डीएमके के मुखिया एमके स्टालिन के एक बयान ने क्ठऊक्रअ गठबंधन को भारी टेंशन में डाल दिया है। स्टालिन ने हाल ही में कहा था कि उनकी पार्टी चुनावी गठबंधन की जरूरतों को लेकर नए सिरे से विचार करेगी। इसके बाद से ही कांग्रेस और विपक्ष के बाकी बड़े नेता डीएमके को मनाने में जुट गए हैं।

# वैभव सूर्यवंशी को आखिर पहले टी-20 में क्यों नहीं मिला मौका? कप्तान अय्यर ने बताई बड़ी वजह

(जीएनएस)।

भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े डेब्यू का इंतजार कर रहे क्रिकेट फैंस को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब मैदान पर आयरलैंड के खिलाफ पहले टी-20 मुकाबले में 15 वर्षीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को भारत की प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया गया है।

इसके चलते महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का 37 साल पुराना ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अब वैभव को रविवार (28 जून) को होने वाले दूसरे टी-20 मुकाबले तक का इंतजार करना होगा। हाल ही में टी-20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद सीनियर टीम के नियमित कॉम्बिनेशन और स्थापित खिलाड़ियों को बिना किसी ठोस तकनीकी कारण के टीम से बाहर करना ड्रेसिंग रूम के संतुलन को प्रभावित कर सकता था। यही कारण है कि चयनकताओं और टीम प्रबंधन ने पहले मुकाबले में जल्दबाजी करने के बजाय अनुभव को तरजीह दी।



शुक्रवार को टॉस के दौरान जब भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर से वैभव सूर्यवंशी के खेलने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने स्थिति स्पष्ट की। कप्तान अय्यर ने कहा कि वैभव एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे आज नहीं खेल रहे हैं। हमारे पास स्क्वॉड में जबरदस्त अनुभवी खिलाड़ी हैं, जिन्होंने पिछली कुछ सीरीज में भारत के लिए अद्भुत प्रदर्शन किया है।

**सही समय पर मिलेगा मौका**

अय्यर ने आगे भरोसा देते हुए कहा कि हम उन खिलाड़ियों को बैक कर रहे हैं जो लगातार शानदार काम कर रहे हैं। वैभव को सही समय आने पर निश्चित रूप से खेलने का अवसर मिलेगा। बता दें कि सचिन तेंदुलकर ने साल 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ 16 साल 205 दिन की उम्र में डेब्यू किया था। वैभव अभी महज 15 वर्ष के हैं।

**बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने दी थी ये दलील**

मैच से पहले भारत के बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने भी वैभव की प्रतिभा की जमकर तारीफ की थी, लेकिन किसी स्थापित खिलाड़ी के साथ नाइंसाफी न करने की बात कही थी। कोटक ने कहा था कि सिर्फ किसी नए खिलाड़ी को मौका देने के लिए उस खिलाड़ी को ड्रॉप कर देना जो पहले से रन बना रहा है सही नहीं होगा। हमें एक बहुत ही बारीक रेखा का ध्यान रखना होता है।

# पाकिस्तान : सैनिटरी पैड्स और टैम्पोन खत्म, फिर भी काफी महंगा! फूड या पैड्स में से एक ही नसीब, भारत में क्या है हाल?

(जीएनएस)।

पाकिस्तान सरकार ने महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सैनिटरी पैड्स और टैम्पोन पर लगने वाला 18 फीसदी सेल्स टैक्स खत्म करने का ऐलान किया है। पाकिस्तान वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि यह महिलाओं के स्वास्थ्य और सम्मान से जुड़ा जरूरी कदम है। हालांकि इस फैसले के बाद एक बड़ा सवाल भी उठ रहा है कि क्या सिर्फ टैक्स हटाने से उन लाखों-करोड़ों महिलाओं की जिंदगी बदल जाएगी, जो आर्थिक तंगी की वजह से आज भी सैनिटरी पैड्स खरीद नहीं पातीं? जानेंगे पाकिस्तान में महिलाओं की दुर्दशा और पीरियड पॉवर्टी का हाल।

यह फैसला अचानक नहीं लिया गया। इसके पीछे सामाजिक कार्यकताओं और महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने वाले लोगों का लंबा संघर्ष रहा। लाहौर हाईकोर्ट में इस मुद्दे पर याचिका भी दायर की गई थी। 'विमेन ऑफ द ईयर' महनूर उमर और अहसान जहांगीर खान ने मांग की थी कि सैनिटरी पैड्स को एक जरूरी स्वास्थ्य उत्पाद माना जाए। लगातार बढ़ते दबाव के बाद सरकार ने आखिरकार इन उत्पादों से 18 फीसदी सेल्स टैक्स हटाने का फैसला लिया।



टैक्स हटाना अच्छी शुरूआत जरूर है, लेकिन पाकिस्तान में पीरियड पॉवर्टी यानी माहवारी से जुड़ी गरीबी की स्थिति बेहद गंभीर है। यूनिसेफ (वठक्उएऋ) के मुताबिक, पाकिस्तान में पीरियड्स वाली सिर्फ 12 फीसदी महिलाएं ही ब्रांडेड सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल कर पाती हैं। यानी करीब 88 फीसदी महिलाएं और लड़कियां आज भी पुराने कपड़ों या असुरक्षित तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हैं। इसका सबसे बड़ा कारण गरीबी, जागरूकता की कमी और सामाजिक रूढ़ियां हैं।

पाकिस्तान में माहवारी को लेकर जागरूकता की कमी का असर लड़कियों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक, हर पांच में से एक लड़की पीरियड्स के दौरान स्कूल जाना छोड़ देती है। ग्रामीण इलाकों में हालात और भी खराब हैं, जहां न साफ शौचालय हैं और न ही सैनिटरी नैपकिन आसानी से उपलब्ध हैं। ऐसे में सिर्फ टैक्स हटाने से यह समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होने वाली।

विशेषज्ञों का कहना है कि 18 फीसदी सेल्स टैक्स हटने से कीमतों में थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन इससे सैनिटरी पैड्स सभी महिलाओं की पहुंच में नहीं आ जाएंगे। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में पैड्स और उनके कच्चे माल पर कुल टैक्स का बोझ अब भी करीब 40 फीसदी है। जब तक सरकार बाकी टैक्स और इम्पोर्ट ड्यूटी में भी कटौती नहीं करेगी, तब तक कीमतों में बड़ी कमी आना मुश्किल है।

पाकिस्तान इस समय गंभीर आर्थिक संकट और महंगाई का सामना कर रहा है। बलूचिस्तान जैसे गरीब इलाकों में एक मां को अपनी तीन बेटियों के लिए हर महीने करीब 40 अमेरिकी डॉलर सिर्फ सैनिटरी पैड्स पर खर्च करने पड़ते हैं। वहीं पाकिस्तान में एक परिवार की औसत मासिक आय करीब 140 अमेरिकी डॉलर है। ऐसे में कई परिवारों के सामने राशन खरीदें या सैनिटरी पैड्स, जैसी मजबूरी खड़ी हो जाती है।

सिर्फ महंगाई ही नहीं, बल्कि समाज की सोच भी बड़ी समस्या है। बलूचिस्तान के क्वेटा और मस्तुंग जैसे इलाकों में कई लड़कियां मेडिकल स्टोर से पैड्स खरीदने में शर्म महसूस करती हैं। वे दुकान खाली होने का इंतजार करती हैं ताकि कोई उन्हें देख न ले।

PRGI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

# लखनऊ में थम नहीं रहा 'अग्नि तांडव': 2 दिन में 2 संस्थानों में आग; 15 मौतों के बाद एक्सपर्ट ने बताई आगजनी की सबसे बड़ी वजह!

(जीएनएस)।

लखनऊः राजधानी में लगातार आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी क्रम में शुक्रवार सुबह कानपुर रोड स्थित लोकबंधु अस्पताल में संचालित वन स्टॉप सेंटर में आग लग गई। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक, यह हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ। जिस समय आग लगी, उस वक्त सेंटर में चार कर्मचारी मौजूद थे। हालांकि, अस्पताल के कर्मचारियों ने सक्रियता दिखाते हुए तुरंत आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया और जल्द ही इस पर काबू पा लिया गया। समय रहते है यदि आग पर काबू नहीं पाया जाता तो यह बड़ी आग की घटना हो सकती थी।

वहीं, इससे पहले 23 जून को ठाकुरगंज स्थित इरम कॉलेज के प्रशासनिक कार्यालय में आग लग गई थी। उस घटना के दौरान मौजूद कर्मचारियों ने भी बताया था कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी, जिसके बाद कार्यालय में रखे कागज और दस्तावेज उसकी चपेट में आ गए, जिससे आग ने गंभीर रूप धारण कर लिया। हालांकि घटना की सूचना मिलने पर पहुंच गई और फायर विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया था। राहत की बात की है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

चीफ फायर ऑफिसर अंकुश मित्तल ने बताया कि दोनों घटनाओं के बारे में जानकारी मिली थी समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। आज की घटना में किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। बता दें कि इससे पहले 22 तारीख को अलीगंज क्षेत्र में भयानक अग्निकांड की घटना हुई थी, जिसमें 15 लोगों की मौत और आधा दर्जन लोग घायल हुए थे। उसके बाद राजधानी में अवैध रूप से संचालित तमाम कोचिंग संस्थान, होटल व ऑफिस को सीज किया गया है।



**घटनाओं को लेकर क्या कहते हैं एक्सपर्ट**

एक्सपर्ट्स का मानना है कि आज के 90% मामले शॉर्ट सर्किट की वजह से होते हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि घर में लगाए जाने वाले उपकरणों और घर में अर्थिंग की सही व्यवस्था की जाए। एक्सपर्ट देवेन्द्र द्विवेदी ने बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से कोई घटना ना हो, इसके लिए बाकायदा सरकार की ओर से नियम भी निर्धारित किए गए हैं। कमर्शियल बिल्डिंगों और औद्योगिक क्षेत्रों में मानकों के तहत वायरिंग और एमसीबी लगाने के नियम हैं।

उन्होंने कहा कि परिसर में ट्रांसफार्मर और अन्य संसाधनों का प्रयोग किया जा रहा है, इसके लिए विद्युत सुरक्षा निदेशालय की ओर से बिजली का कनेक्शन देने से पहले एनओसी लेने की व्यवस्था अनिवार्य है, लेकिन यह व्यवस्था सिर्फ खानापूर्ति बनकर रह गई है। एनओसी के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाता है और बिना जमीनी सत्यापन के ही बिल्डिंग को एनओसी मिल जाती है। ऐसे में यह सुनिश्चित नहीं हो पाता है कि बिल्डिंग में मानकों के अनुसार बिजली के उपकरण लगे हैं या नहीं।

बिना जांच के बिजली विभाग इन बिल्डिंगों को बिजली का कनेक्शन दे देता है। ऐसे में कई बार लोड बढ़ने की वजह से वायर हीट हो जाते हैं और मानकों के अनुरूप एमसीबी न लगी होने से वह ट्रिप नहीं करती है, जिससे शॉर्ट सर्किट जैसी घटनाएं होती हैं और यही शॉर्ट सर्किट की घटनाएं बाद में बड़ी आग का रूप ले लेती है।

# वीडियो कॉल पर बेटी की विदाई देख थमी पिता की धड़कन, लखनऊ के अस्पताल में भर्ती थे लालबाबू

(जीएनएस)।

सोनबरसा (सीतामढ़ी)। कहते हैं एक पिता के जीवन का सबसे बड़ा और भावुक क्षण वह होता है, जब वह अपनी लाडली का कन्यादान करता है। अपनी पाई-पाई जोड़कर बेटी को रानी की तरह विदा करने का ख्वाब हर बाप देखता है।

सोनबरसा बस स्टैंड के रहने वाले लालबाबू महतो की आंखों में भी अपनी सबसे छोटी बेटी निधि के लिए यही अरमान तैर रहे थे। बुधवार की रात निधि के हाथ पीले हुए, घर में शहनाइयां गूंजीं, लेकिन नियति की लिखी स्क्रिप्ट इतनी क्रूर थी कि जिसे सुनकर पूरा इलाका सिसक उठा।

इधर बेटी की डोली उठी, और उधर सैकड़ों किलोमीटर दूर लखनऊ के एक अस्पताल में वीडियो कॉल पर यह विदाई देख रहे पिता ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लीं।

**नम आंखें और स्क्रीन पर 'वरमाला'**

लालबाबू महतो सालों तक बस में कन्डक्टरी (कंडक्टरी) कर अपने परिवार का पेट पालते रहे। तीन बेटों और दो बेटियों के इस भरे-पूरे परिवार में सबसे छोटी बेटी निधि की शादी को लेकर वो बेहद उत्साहित थे।



तैयारियां जोरों पर थीं, लेकिन शादी से ठीक तीन दिन पहले अचानक उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें आनन-फानन में लखनऊ के एक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उनके साथ पत्नी मीनू देवी और बेटा राजेश भी लखनऊ चले गए।

घर पर सिसकियां थीं, लेकिन लालबाबू की ही जिद थी कि बेटी की शादी तय तारीख पर ही हो। बुधवार की रात सीतामढ़ी में विवाह की रस्में शुरू हुई।

लखनऊ के आईसीयू बेड पर लेटे लालबाबू के सामने मोबाइल की स्क्रीन ऑन थी। वीडियो कॉल के जरिए उन्होंने अपनी लाडली को दुल्हन बनते देखा। जब निधि ने दूल्हे को वरमाला पहनाई, तो अस्पताल के बेड पर बेबस पड़े पिता की आंखें खुशी और लाचारी के आंसुओं से छलक उठीं।

जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए भी एक पिता की सांसें सिर्फ इसलिए अटकी थीं, ताकि वह अपनी लाडली को विदा होते देख सके।

**आंसुओं के साथ थम गई पिता की सांसें**

गुरुवार की सुबह करीब 9 बजे का वक्त था। विवाह संपन्न हो चुका था और अब निधि की विदाई की बेला थी। मायके से पैर भारी कर जैसे ही निधि डोली (गाड़ी) में बैठी, लखनऊ के अस्पताल में वीडियो कॉल की स्क्रीन पर लालबाबू महतो फफक कर रो पड़े।

उधर बेटी बाबुल का घर छोड़ रही थी, इधर पिता इस नश्वर संसार को छोड़ने की तैयारी कर रहा था। दिल को झकझोर देने वाली बात यह रही कि जैसे ही निधि की विदाई का वीडियो कॉल कटा, उसके कुछ ही मिनटों बाद लालबाबू महतो की धड़कनें हमेशा के लिए शांत हो गईं।

निधि के ससुराल पहुंचते ही पिता के निधन की खबर आ गई। जिस घर से कुछ देर पहले मंगलगीत गाकर बेटी को विदा किया गया था, वहां अब चित्कार गूंज रही थी।

लाडली की डोली उठने का इंतजार शायद लालबाबू की आखिरी सांसें भी कर रही थीं, और फर्ज पूरा होते ही वो अनंत यात्रा पर निकल गए।

# आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे हादसा, ट्रेलर से टकराई बस, 2 की मौत, 25 यात्रियों को किया गया रेस्क्यू

**आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस द्वारा ट्रेलर में टक्कर मारी गई। हादसे में 2 लोगों की मौत दर्ज की गई है और 25 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।**

(जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर रफ्तार का भयानक कहर देखा गया है। थाना नगला खंगर क्षेत्र के अंतर्गत एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन संख्या 63 के पास हुए एक भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 25 यात्रियों को गंभीर रूप से घायल अवस्था में रेस्क्यू किया गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि डबल डेकर स्लीपर बस के अगले हिस्से को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त पाया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, करीब 60 यात्रियों से भरी एक निजी डबल डेकर स्लीपर बस को गोरखपुर से चंडीगढ़ की तरफ ले जाया जा रहा था। जैसे ही बस को नगला खंगर इलाके में लाया गया, तभी उसे अचानक आगे चल रहे



एक ट्रेलर (ट्रक) में पीछे से टकराते हुए देखा गया। शुरूआती जांच और चश्मदीदों के बयानों के आधार पर यह माना जा रहा है कि तेज रफ्तार के दौरान बस चालक को अचानक नींद की झपकी आ गई थी, जिसके कारण वाहन से नियंत्रण खो दिया गया।

**रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर निकाले गए यात्री**

दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस और यूपीडा (वढएकळ्ळ) की रेस्क्यू टीमों द्वारा एम्बुलेंस के साथ तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया गया। पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए बस की खिड़कियों और क्षतिग्रस्त मलबे में फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।

**घायलों को कराया गया अस्पताल में भर्ती**

हादसे में घायल हुए 25 यात्रियों को तत्काल शिकोहाबाद के संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। इनमें से 5 यात्रियों की हालत बेहद नाजुक पाई गई, जिसके चलते उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है, जहाँ उनका उपचार किया जा रहा है। बाकी बचे यात्रियों की हालत फिलहाल स्थिर बताई गई है।

**चालक और सह-चालक के शवों को भेजा गया पोस्टमार्टम**

इस संबंध में जानकारी देते हुए सिरसागंज के सीओ चंचल त्यागी द्वारा बताया गया कि दुर्घटना में जान गंवाने वाले दोनों व्यक्ति बस के चालक और सह-चालक (कंडक्टर) हैं। पुलिस द्वारा दोनों शवों का पंचनामा भरकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। क्षतिग्रस्त वाहनों को एक्सप्रेसवे से हटाकर यातायात को सुचारू रूप से बहाल कर दिया गया है। फिलहाल, पुलिस द्वारा मामले की आगे की जांच की जा रही है।

# लखनऊ में शेयर ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा देकर 3.27 करोड़ की ठगी, मुकदमा दर्ज

(जीएनएस)।

लखनऊ। शेयर ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा देकर साइबर ठगों ने ठेकेदार से से 3.27 करोड़ रुपये ऐंठ लिए। फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर जालसाज युवती ने खुद को यूएस की ट्रेडिंग कंपनी का अधिकारी बताकर फंसाया। ट्रेडिंग कराकर डीमैट अकाउंट में करीब दस करोड़ का मुनाफा दिखाया गया।

विड्राल पर टैक्स समेत अन्य मदों के नाम पर रुपये जमा कराकर उन्हें ब्लाक कर दिया गया। एडीसीपी क्राइम किरन यादव के आदेश पर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

अलीगंज सेक्टर-एन निवासी निजी फर्म के मालिक दीपक अग्रवाल जल निगम के ठेकेदार हैं। अक्टूबर 2025 में दीपक ने फेसबुक पर एक युवती से बातचीत शुरू की।

बातचीत के दौरान जालसाज ने व्यापार के बारे में पूछा और खुद को डिजिटल गोल्ड मिरेकल कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर बताया। उक्तदीपक ने 25 नवंबर को 40 हजार रुपये का निवेश कर ट्रेडिंग की। कुछ दिन बाद डीमैट अकाउंट में दस लाख यूएस डालर (9.65 करोड़) का मुनाफा दिखाया गया।



# यौमे आशूरा पर 'या हुसैन' 'या अब्बास' के नारों से गुंजा लखनऊ

**आज पूरी दुनिया में इमाम हुसैन के चाहने वाले उन्हें याद कर, मातम कर रहे हैं**

(जीएनएस)।

लखनऊ/सिद्धार्थनगर/बरेलीः राजधानी लखनऊ में नाज़िम अली इमामबाड़े से शुक्रवार को यौमे आशूरा का ऐतिहासिक जुलूस निकाला गया। जुलूस में हजारों की तादाद में अजादार शामिल हुए. इस दौरान "या हुसैन", "या सकीना", "या अब्बास" और "या मौला अली" के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। सिद्धार्थनगर में भी मोहर्रम का पर्व बड़े ही अकीदत और गमगीन माहौल में मनाया गया. हजरत इमाम हुसैन की याद में आजादारों ने भव्य जुलूस निकाला और मातम किया. बरेली के बहेड़ी नगर में मोहर्रम के अवसर पर ताजियों की अधिकतम ऊंचाई 12 फीट निर्धारित किए जाने के बाद, सभी ताजिए को इमामबाड़ों में ही रखे गए. जुलूस की नेतृत्व मशहूर आलिम-ए-दीन मौलाना कल्बे जवाद ने की.

ईटीवी भारत से बातचीत में मौलाना कल्बे जवाद ने कहा कि जब हजरत इमाम हुसैन से पूछा गया कि वह किस मुल्क में जाना पसंद करेंगे, तो उन्होंने किसी मुस्लिम देश का नहीं, बल्कि हिंदुस्तान का नाम लिया था. उन्होंने कहा कि "हिंदुस्तान से हमें अपनी वतन की खुशबू आती है."

उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वालों की बड़ी तादात है. झांसी की रानी के नाम का ताज़िया, महाराजा बनारस के नाम का ताज़िया और कई हिंदू राजाओं के नाम से आज भी ताज़िए रखे जाते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि मुंशी प्रेमचंद ने 'इमाम हुसैन' शीर्षक से कर्बला पर पुस्तक लिखी, जो गंगा-जमुनी तहजीब और आपसी भाईचारे की मिसाल है.

मौलाना ने कहा कि आज पूरी दुनिया में इमाम हुसैन के चाहने वाले उन्हें याद कर, मातम कर रहे हैं. लखनऊ की अवाम भी सड़कों पर उतरकर "या हुसैन", "या अली" के नारे लगाते हुए कर्बला तक जाएंगे, जहां ताज़िए दफन किए जाएंगे. जुलूस के दौरान कुछ बच्चों के हाथों में ईरान के सर्वोच्च नेता सैयद अली खामेनेई की तस्वीरें भी दिखाई दीं.



प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए मौलाना कल्बे जवाद ने कहा कि भीषण गर्मी के बावजूद इस बार सड़कों पर पानी का छिड़काव नहीं कराया गया, जबकि, हर साल ऐसा किया जाता था. उन्होंने कहा कि सड़कें इतनी गर्म हैं कि लोगों के पैरों में छाले पड़ रहे हैं. इसे उन्होंने प्रशासन की बड़ी लापरवाही बताया.

फिरोजाबाद में पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी द्वारा ताज़ियों को इंची टेप से नापे जाने के मामले पर भी उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और यह मुख्यमंत्री के निर्देशों की भी अवहेलना है.

वहीं, मौलाना सैफ अब्बास ने ईटीवी भारत से कहा कि इंसानियत की हिफाजत के लिए हजरत इमाम हुसैन ने अपनी और अपने परिवार की कुर्बानी दी थी. उसी कुर्बानी की याद में दुनिया भर के लोग आज सड़कों पर निकलते हैं.

उन्होंने कहा कि सभी धर्मों और समुदायों के लोग बिना किसी भेदभाव के इमाम हुसैन को याद करते हैं. मौलाना ने कहा कि जिस तरीके से ताजिए को इंची टेप से नापा जा रहा है, इस तरीके से कावड़ यात्रा में भी इंची टेप लेकर, क्या यह पुलिस अधिकारी सड़क पर उतरेंगे.

मौलाना सैफ अब्बास ने कहा कि दुनिया भर में लोग अपने बच्चों का नाम हुसैन रखते हैं, कोई अपने बच्चे का नाम यजीद नहीं रखा. उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे बच्चे भी जंजीरी मातम कर रहे हैं. एक मां अपने बच्चे की उंगली कटने पर भी तड़प उठती है, लेकिन यहां बच्चे जंजीरी मातम करते हैं और जब उनके कपड़े खून से भीग जाते हैं. तो उनकी माएं इसे इमाम हुसैन की मोहब्बत और अकीदत का प्रतीक मानती हैं.

मौलाना सैफ ने कहा कि भीषण गर्मी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि वे कर्बला के उस मैदान को याद करते हैं जहां हजरत इमाम हुसैन और उनके परिवार ने शहादत दी थी. उन्होंने कहा कि जुलूस की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं. बड़ी संख्या में पुलिस, पीएसी, आरएएफ और अन्य सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है. शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस नाज़िम अली इमामबाड़े से करीब तीन किलोमीटर दूर कर्बला तालकटोरा की ओर बढ़ा है.

जुलूस में इस बार मेवे से तैयार किया गया एक अनोखा अलम भी आकर्षण का केंद्र रहा. करीब 50 किलोग्राम मेवों से तैयार इस अलम में मखाना, खजूर, छुहारा, बादाम, अंजीर और नारियल का इस्तेमाल किया गया है, जिसे कर्बला तालकटोरा ले जाया गया. इसके अलावा चांदी के अलम भी जुलूस में शामिल है. गुलाब के फूलों से सजे जुलूस में बड़ी संख्या में युवा नौहा पढ़ते और मातम करते हुए कर्बला की ओर बढ़ते दिखाई दिए.

अकबरी गेट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. यहां भारी संख्या में पुलिस बल, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाएं तैनात हैं. मीनारा मस्जिद पर सुन्नी समुदाय का पारंपरिक कार्यक्रम भी आयोजित हुआ, जबकि शिया समुदाय का जुलूस अकबरी गेट से होकर कर्बला तालकटोरा पहुंचा. प्रशासन ने एहतियात के तौर पर अकबरी गेट पर बड़ा पर्दा भी लगाया और सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह चाक-चौबंद रखा.

सिद्धार्थनगर में इमाम हुसैन की याद में निकाला गया जुलूसः वहीं, सिद्धार्थनगर में मोहर्रम का पर्व बड़े ही अकीदत और गमगीन माहौल में मनाया गया. उपनगर हल्लौर में श्रद्धालुओं ने भव्य जुलूस निकाला और हजरत इमाम हुसैन (र.अ.) की शहादत को याद करते हुए मातम किया. जुलूस में बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए. मातम करने वाले श्रद्धालुओं ने कहा कि पूरी दुनिया में अमन व शांति कायम रहे, इसी उद्देश्य से हजरत इमाम हुसैन ने कर्बला के मैदान में अन्याय व जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की और अपनी जान की कुर्बानी दे दी.

बरेली में ताजिए को इमामबाड़ों में ही रखे गएः बरेली के बहेड़ी नगर में मोहर्रम के अवसर पर ताजियों की अधिकतम ऊंचाई 12 फीट निर्धारित किए जाने के बाद, नगर प्रमुख ताजिए जुलूस में शामिल नहीं हुए, सभी ताजिए को इमामबाड़ों में ही रखे गए, जिससे हर वर्ष लगने वाला नैनीताल रोड का मेला भी नहीं लग सका.

# लखनऊ में 3 जुलाई से शुरू होगा 'यूपी आम महोत्सव', किसानों को कमाई का मिलेगा नया प्लेटफॉर्म

**उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 3 से 5 जुलाई तक लखनऊ में आयोजित होगा, जिसका उद्देश्य आम को राष्ट्रीय पहचान दिलाना और किसानों को बेहतर विपणन अवसर प्रदान करना है।**

(जीएनएस)।

मैनपुरी। प्रदेश की प्रमुख बागवानी फसल आम को राष्ट्रीय पहचान दिलाने और किसानों को बेहतर विपणन अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तीन दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव का आयोजन तीन से पांच जुलाई तक लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया जाएगा। उद्यान विभाग ने जिले के प्रगतिशील आम उत्पादकों से महोत्सव में सक्रिय भागीदारी करने की अपील की है।



जिला उद्यान अधिकारी श्याम सिंह ने बताया कि महोत्सव में प्रदेश की उत्कृष्ट और व्यावसायिक आम की विभिन्न किस्मों के साथ आम से तैयार प्रसंस्कृत उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा।

**किसानों को मिलेगा नए अवसर तलाशने का मौका**

कार्यक्रम के दौरान किसानों, व्यापारियों, निर्यातकों और विशेषज्ञों के बीच खरीदार-विक्रेता बैठकें आयोजित होंगी, जिससे किसानों को बाजार से जुड़ने और नए अवसर तलाशने का मौका मिलेगा।

उन्होंने बताया कि आम से बने उत्पाद, आकर्षक पैकेजिंग और वैल्यू एडिशन तकनीकों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। प्रदर्शनी में शामिल होने के लिए किसानों को अपने आम के नमूने दो जुलाई सुबह 10 बजे तक लखनऊ भेजने होंगे। उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले आमों को पुरस्कृत किया जाएगा, साथ ही किसान अपने उत्पादों की बिक्री भी कर सकेंगे।

# लखनऊ के अलीगंज कोचिंग सेंटर अग्निकांड में अधिशासी अभियंता के सस्पेंशन पर बिजली संगठनों ने किया प्रदर्शन

**संघर्ष समिति ने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन से मांग की है कि संबंधित अभियंता का सस्पेंशन तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए।**

(जीएनएस)।

लखनऊः लखनऊ के अलीगंज स्थित कोचिंग सेंटर अग्निकांड की जांच में पावर कॉरपोरेशन के अधिशासी अभियंता पर की गई निलंबन की कार्रवाई पर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है।

समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि इस दुखद घटना के लिए वास्तविक जिम्मेदारियों की निष्पक्ष जांच किए बिना अधिशासी अभियंता (कलेक्शन) को निलंबित करना पूरी तरह अन्यायपूर्ण, तथ्यहीन और बलि का बकरा बनाने की कार्रवाई है।

संघर्ष समिति ने उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन से मांग की है कि संबंधित अभियंता का सस्पेंशन तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए.




संघर्ष समिति के संयोजक शैलेन्द्र दुबे का कहना है कि यह तथ्य प्रमुखता से सामने आया है कि संबंधित भवन में विद्युत सुरक्षा के समुचित इंतजाम नहीं थे और भवन का आवश्यक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट भी नहीं कराया गया था.

एफआईआर जांच के दौरान विद्युत सुरक्षा विभाग के अधिकारी यह अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके कि भवन का विद्युत सुरक्षा ऑडिट कब किया गया था या या घटना से पूर्व भवन की विद्युत सुरक्षा की जांच कब की गई थी? यह स्थिति स्पष्ट रूप से विद्युत सुरक्षा निदेशालय और अन्य संबंधित एजेंसियों की गंभीर लापरवाही को दर्शाती है.

संघर्ष समिति ने कहा कि अगर किसी भवन में विद्युत सुरक्षा मानकों का अनुपालन नहीं किया गया, विद्युत सुरक्षा ऑडिट नहीं हुआ. अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं अपर्याप्त थीं और संबंधित विभागों ने समय-समय पर निरीक्षण नहीं किया तो इन गंभीर कमियों की जिम्मेदारी निर्धारित किए बिना सिर्फ विद्युत वितरण निगम के एक अभियंता को दोषी ठहराना न्यायोचित नहीं कहा जा सकता.

संघर्ष समिति ने कहा कि निलंबन आदेश में स्वीकृत भार से अधिक विद्युत भार उपयोग किए जाने का आरोप लगाया गया है, जबकि उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार परिसर का विद्युत भार वर्ष 2016 में विधिवत रूप से 20 किलोवाट तक बढ़ाया जा चुका था.

अप्रैल, मई और जून में भार वृद्धि की स्थिति की जानकारी मासिक बिलिंग और मास्टर डाटा के माध्यम से बाद में प्राप्त होती है. नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई अगले माह उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर ही की जा सकती है. ऐसी स्थिति में जुलाई से पूर्व बढ़े हुए भार के आधार पर किसी अधिकारी को दोषी ठहराना नियम सम्मत नहीं है.

समिति के पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि विद्युत वितरण निगम की जिम्मेदारी उपभोक्ता को विधिवत कनेक्शन उपलब्ध कराना और निर्धारित मानकों के अनुरूप विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना है. भवन के अंदर की वायरिंग, विद्युत उपकरणों की गुणवत्ता, विद्युत सुरक्षा प्रमाणन, अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन और समय-समय पर सुरक्षा परीक्षण की जिम्मेदारी भवन स्वामी और संबंधित नियामक व सुरक्षा एजेंसियों की होती है.

इन दायित्वों की उपेक्षा कर एक अभियंता के विरुद्ध कार्रवाई करना वास्तविक तथ्यों से ध्यान हटाने का प्रयास है. किसी भी दुर्घटना की निष्पक्ष और तकनीकी जांच पूरी होने से पूर्व दंडात्मक कार्रवाई करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है.

# गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा- 'यूपी में 12 करोड़ से अधिक लोगों को फ्री में मिल रही स्वास्थ्य की सुविधा'

**मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार में हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं.**

(जीएनएस)।

गोरखपुर : जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को एक निजी अस्पताल का उद्घाटन किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में स्वास्थ्य सुविधा की बेहतरी के लिए बड़े काम हुए हैं. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 12 करोड़ से अधिक लोगों को फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा मिल रही है.

"लोगों के परसेप्शन को बदला" : उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार में हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं जबकि, पिछली सरकारों में माफिया पैदा किए जाते थे. उन्होंने कहा कि क्वालिटी हेल्थ फैसिलिटी (गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा) आज की आवश्यकता है. इसी के दृष्टिगत वर्ष 2017 के बाद स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा के गुणवत्तापूर्ण विस्तार के जरिये सरकार ने प्रदेश के प्रति लोगों के परसेप्शन को बदला है.

"प्रदेश को दिया योजनाओं का उपहार" : उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों और वर्तमान सरकार के बीच सबसे बड़ा अंतर यही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने 'वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया' दिया था. जबकि हमारी सरकार ने 'वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज', (एक जिला एक मेडिकल कॉलेज) 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' (एक जिला एक उत्पाद) और 'वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन' (एक जिला एक व्यंजन) जैसी योजनाओं का उपहार प्रदेश को

दिया है. इन योजनाओं से प्रदेश के प्रति धारणा बदलने, नई और मजबूत पहचान बनाने में मदद मिली है.

पांच लाख रुपये तक के इलाज की मुफ्त सुविधा : मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र का उन्नयन सरकार की प्राथमिकता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में समूचे विश्व की सबसे बड़ी स्कीम आयुष्मान भारत संचालित हो रही है. इस स्कीम में जो तबके छूट गए, उन्हें यूपी सरकार ने राज्य स्तर पर कवर किया. इस योजना में लाभार्थियों को पांच लाख रुपये तक के इलाज की सुविधा मुफ्त मिलती है.

सीएम योगी ने बताया कि इसके अलावा जरूरतमंद लोगों के इलाज के लिए प्रति वर्ष वह 1200 से 1500 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष से देते हैं.

"हर जिले में मेडिकल कॉलेज की सौगात" : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 के बाद से प्रदेश में व्यापक परिवर्तन देखने को मिल रहा है. बिना भेदभाव सबको सुरक्षा, सम्मान और शासन की सुविधाओं का लाभ मिल रहा है. उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज की सौगात दी है. पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में एकमात्र गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज था, जो 2017 के पूर्व खुद ही बीमार था. वास्तव में बीआरडी मेडिकल कॉलेज बीमार नहीं था बल्कि तत्कालीन सरकारों की मानसिकता बीमार थी जिन्होंने यहां की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया था.

"गोरखपुर में एम्स की भी सुविधा" : उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के लिए कुछ भी नहीं किया था. उन्होंने बताया कि आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज बेहतरीन तरीके से संचालित हो रहा है तो गोरखपुर में एम्स की भी सुविधा मिल रही है. सीएम ने कहा कि गोरखपुर के अलावा महाराजगंज, देवरिया, सिद्धार्थनगर, बस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, आजमगढ़, गाजीपुर, रायबरेली, अमेठी, मिजार्पुर, चंदौली में मेडिकल कॉलेज बन गए हैं. इन मेडिकल कॉलेज में क्लास के साथ हॉस्पिटल भी बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं. बलिया में भी मेडिकल कॉलेज को स्वीकृति मिल चुकी है.

"दो दर्जन से अधिक अस्पतालों में आईसीयू की सुविधा" : उन्होंने कहा कि आज गोरखपुर में दो दर्जन से अधिक अस्पताल ऐसे हैं जहां आईसीयू की सुविधा है. मुख्यमंत्री ने बताया कि 2007 में गोरखनाथ हॉस्पिटल में 10 बेड के साथ पहली बार आईसीयू की सुविधा शुरू हुई थी. ब्लड सेपरेटर मशीन और डायलिसिस मशीन भी पहली बार गोरखनाथ हॉस्पिटल में ही लगाई गई. आज निजी के साथ ही सरकारी अस्पतालों में बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध हैं.

# 'पहले की सरकार हर जिले में माफिया पालती थी, हमने मेडिकल कॉलेज दिए'; गोरखपुर में बोले सीएम योगी

**मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एस्ट्रोमेडिक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के लोकार्पण पर पिछली सरकारों पर माफिया पालने का आरोप लगाया। ...**

(जीएनएस)।

गोरखपुर। मुख्यमंत्री ने एस्ट्रोमेडिक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के लोकार्पण समारोह में स्वास्थ्य सेवाओं में हुए बदलाव को सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें प्रदेश के प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज नहीं दे सकीं, बल्कि 'हर जिले में एक माफिया पालने" का काम करती थीं, जबकि उनकी सरकार ने 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन मेडिकल कॉलेज' की अवधारणा को साकार कर प्रदेश की तस्वीर बदल दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल थी। उस समय गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज स्वयं बीमार था। उन्होंने कहा कि बीमार मेडिकल कॉलेज नहीं था, बल्कि तत्कालीन सरकारों की मानसिकता बीमार थी, जिसने पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को इलाज के अभाव में मरने के लिए छोड़ दिया था। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में कोई ठोस कार्य नहीं किया गया।

उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के लगभग हर जिले में मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं। गोरखपुर के साथ-साथ महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, अंबेडकरनगर, बलिया, गाजीपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, मिजार्पुर और

चंदौली सहित सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा चुके हैं और वहां पढ़ाई तथा अस्पताल दोनों संचालित हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश के मरीज इलाज के लिए दिल्ली, मुंबई और लखनऊ की ओर पलायन करने को मजबूर थे। एम्स दिल्ली में पूर्वांचल और बिहार के मरीजों की लंबी कतारें लगी रहती थीं क्योंकि क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था। उन्होंने याद दिलाया कि वर्ष 2005 में गोरखपुर में आईसीयू, डायलिसिस और प्लेटलेट्स सेपरेशन जैसी बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं थीं।

वर्ष 2007 में गोरखनाथ चिकित्सालय में पहला 10 बेड का आईसीयू, पहली डायलिसिस मशीन और पहली ब्लड सेपरेटर यूनिट स्थापित कराई गई थी। आज गोरखपुर में दो दर्जन से अधिक अस्पताल अत्याधुनिक आईसीयू सुविधाओं से लैस हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल मुफ्त इलाज नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। आयुष्मान भारत योजना और राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में लगभग 12 करोड़ लोगों को निशुल्क उपचार की सुविधा मिल रही है। मुख्यमंत्री राहत कोष से भी हर वर्ष 1200 से 1500 करोड़ रुपये गंभीर बीमारियों से जूझ रहे गरीब मरीजों के इलाज पर खर्च किए जा रहे हैं।

**मार्कण्डेय चन्द को सीएम ने दी श्रद्धांजलि**

मुख्यमंत्री ने एस्ट्रोमेडिक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल की सराहना करते हुए कहा कि गोरखपुर के हृदयस्थल बेतियाहाता में स्थापित यह अस्पताल फोर्टिस हॉस्पिटल के सहयोग से संचालित होगा और सुपर स्पेशियलिटी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएगा।

उन्होंने अस्पताल के संस्थापक स्वर्गीय मार्कण्डेय चन्द को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया और जीवनभर गोरखपुर तथा गोरक्षपीठ के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय मार्कण्डेय चन्द के पुत्र सीपी चन्द और डॉ. अरुण चन्द ने अपने पिता की स्मृति को जीवंत रखते हुए पूर्वांचल को आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का नया केंद्र दिया है। उन्होंने विश्वास जताया कि एस्ट्रोमेडिक्स न केवल लोगों को बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराएगा बल्कि रोजगार सृजन और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

# नोएडा-ग्रेटर नोएडा में भारी वाहनों की 'नो एंट्री', सीएम योगी के आगमन को लेकर ये रूट रहेंगे डायवर्ट

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गौतमबुद्ध नगर दौरे के कारण शनिवार को नोएडा-ग्रेटर नोएडा में यातायात डायवर्जन लागू रहेगा।

(जीएनएस)।

ग्रेटर नोएडा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शनिवार को गौतमबुद्ध नगर आना हो रहा है। इसके चलते यातायात पुलिस ने कुछ मार्गों पर रूट डायवर्जन लागू किया है। जबकि नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे, यमुना एक्सप्रेस-वे व आसपास के मार्गों पर सुबह सात से रात 10 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस ने वाहन चालकों से वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करने की अपील की है।

**इन रास्तों पर भारी वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी**

दिल्ली सीमा (चिल्ला, डीएनडी, कालिंदी कुंज) से गौतमबुद्धनगर में भारी मालवाहक वाहन , मध्यम मालवाहक वाहन और हल्के मालवाहक वाहन का प्रवेश सुबह सात से रात 10 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा।

**यह हैं वैकल्पिक मार्ग**

चिल्ला बॉर्डरः नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे व यमुना एक्सप्रेस-वे जाने वाले वाहन चिल्ला रेड लाइट से यू-टर्न लेकर एनएच-9/24 से एनएच-91 व ईस्टर्न पेरिफेरल होकर जा सकेंगे।

डीएनडी बार्डरः डीएनडी टोल प्लाजा से यू-टर्न लेकर एनएच-9/24 से एनएच-91 व ईस्टर्न पेरिफेरल से गंतव्य तक जा सकेंगे।

कालिंदी कुंजः एनएच-9/24 से लेकर ईस्टर्न पेरिफेरल व एनएच-91 होकर आगे जा सकेंगे।

**यमुना एक्सप्रेस-वे पर डायवर्जन**

आगरा से आने वाले वाहनों को जेवर टोल से पहले ही यू-टर्न लेकर

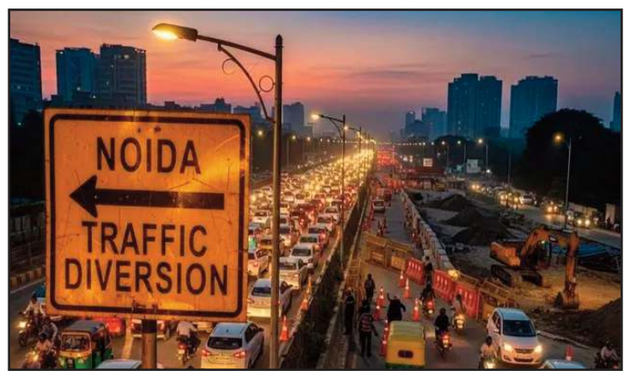


अलीगढ़ की ओर डायवर्ट किया जाएगा।

दबाव अधिक होने पर वाहनों को जेवर से जहांगीरपुर की ओर खुर्जा, सिकंदराबाद, बुलंदशहर होकर भेजा जाएगा।

परीचौक से आगरा जाने वाले वाहन एल्डिको कामर्शियल गोलचक्कर से मेट्रो डिपो गोलचक्कर व 130 मीटर रोड होकर सिरसा गोलचक्कर से ईस्टर्न पेरिफेरल से जा सकेंगे।

नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे पर दबाव बढ़ने पर वाहन डायवर्ट सर्विस मार्ग पर किए जाएंगे।

**कार्यक्रम स्थल सेक्टर-10**

**यीडा जाने वाले रूट**

दनकौर, रौनीजा/गौर सिटी से आने वाले वाहन भाइपूरा चौराहे से बाएं, रघुपुरा कस्बा होकर काकी तिराहे से दाहिने, रघुपुरा बाईपास रोड से बीकानेर मिठास भंडार से बाएं मुड़कर पहुंचें।

कस्बा जेवर से आने वाले वाहन टील से यमुना एक्सप्रेस-वे से फलेदा कट (27 किमी) से उतरकर दाहिने टर्न कर फलेदा अंडरपास होकर डबल सर्विस रोड से भाइपूरा चौराहे से बाएं मुड़कर रघुपुरा होते हुए पहुंचें।

**सेक्टर-आठ यीडा कार्यक्रम के लिए रूट**

कच्चा जेवर से आने वाले वाहन खुर्जा अंडरपास होकर जेवर-जहांगीरपुर-खुर्जा मार्ग से परौही रोड होकर पहुंचें।

दनकौर-रबूपुरा से आने वाले वाहन रबूपुरा से झाझर रोड होते हुए आकलपुर से मौकनपुर में नहर की पटरी होकर पहुंचें।

**यह रहेगी पार्किंग व्यवस्था**

सेक्टर-10 यीडाः वीवीआईपी पार्किंग मंच के पीछे, विशिष्ट की पार्किंग वीवीआईपी के बायें सर्विस रोड पर, मीडिया व बस पार्किंग टीआई पार्किंग के बराबर सर्विस रोड पर, कर्मी व पुलिस पार्किंग पी-2, पी-3, पी-4 के आसपास निर्धारित की गई है।

सेक्टर-आठ यीडाः वीवीआईपी पार्किंग मंच के बाएं, पुलिस, अग्नि शमन की पार्किंग मंच के बाएं परांठी रोड के किनारे, सामान्य पार्किंग मंच के बाएं परांठी रोड के किनारे होगी।

अपोलो अस्पताल सेक्टर-86 नोएडाः वीवीआईपी पायलट पार्किंग नोएडा विकास प्राधिकरण के नवीन कार्यालय सेक्टर-96, अतिविशिष्टों की पार्किंग महामाया बालिका इंटर कालेज के गेट नंबर-4 के अंदर, सामान्य/पुलिस पार्किंग स्क्वायर माल सेक्टर-80 में रहेगी।

**असुविधा होने पर हेल्पलाइन नंबर पर करें संपर्क**

डीसीपी ट्रैफिक अभय कुमार मिश्र ने बताया कार्यक्रम के दौरान आपातकालीन वाहनों को सुगम पास कराया जाएगा। असुविधा होने पर यातायात हेल्पलाइन नंबर 9971009001 पर संपर्क करें।

# 'राहुल-अखिलेश किस मुंह से जनता के बीच जाएंगे...', सीएम योगी ने विरोधी दलों पर साधा निशाना

**सीएम योगी ने सपा-कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इनकी सरकारों में लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी जाती थी. बाबा साहब के संविधान को अपमानित करने का काम किया जाता था.**

(जीएनएस)।

संत कबीर नगर,

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर एक बार फिर से बड़ा हमला किया हैं. गुरुवार को सीएम योगी संतकबीर नगर दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव किस मुंह से लोगों के बीच जाते हैं ये लोग 2024 में संविधान की प्रति लेकर घूमते थे. जबकि, संविधान की हत्या का काम भी इन्हीं लोगों ने किया था.

सीएम ने कहा- 25 जून, 1975 को इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या की थी. अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, मुलायम सिंह यादव जैसे नेताओं को जेल में डाल दिया था. आपातकाल लगाकर देश के नेताओं को जेल में डालने का काम किया था, क्योंकि इन नेताओं ने लोकतंत्र की वकालत की थी.

**विरोधी दलों पर सीएम योगी साधा निशाना**

मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा-कांग्रेस की सरकारों में लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी जाती थी. मतदान करने पर भी रोक लगा दी जाती थी. बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को अपमानित करने का काम किया जाता था. आप लोगों को याद हो होगा कि 2024 के चुनाव में संविधान की प्रति लेकर सपा और कांग्रेस के लोग लोगों को गुमराह कर रहे थे.

भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने गांव, गरीब, किसान, महिला, पुरुष, युवा, बुजुर्ग सबको सम्मान देने का काम किया है. आज गरीब को उनकी छत देने का काम डबल इंजन सरकार ने किया है.

**डबल इंजन सरकार के कामों की तारीफ**

योगी ने कहा- जब अच्छी सरकारी आती हैं और अच्छी जनप्रतिनिधि आते हैं तो काम होता है. जब बेईमानों और भ्रष्टाचारियों की सरकार आती है वे जनता के हक में डाका डालते हैं. गरीबों-पिछड़ों का हक छीनते हैं. किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते हैं और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते है. यूपी आज भारत की ऊंची अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन माना जाता है.

संत कबीर नगर में कबीर दास जी आए थे. इसी जिले को पहले माना जाता था कि मगहर में मरना पाप होता है लेकिन, यहां ऑडिटोरियम और एकेडमी हैं। जैसे ही आमी नदी पार करेंगे तो गोरखपुर का औद्योगिक क्षेत्र शुरू हो जाता है जिसमें मगहर के लोगों को वहां पर रोजगार मिल रहे हैं. जहां डिग्री कॉलेज नहीं थे, वहां कॉलेज खोले जा रहे हैं.

**करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास**

मुख्यमंत्री ने इस दौरान संतकबीर नगर की धनघटा और गोरखपुर जिले की खजनी विधानसभा क्षेत्र के लिए कुल 475 करोड़ रुपये की 139 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इनमें संतकबीर नगर में 54.42 करोड़ की 17 परियोजनाओं का लोकार्पण, 170.37 करोड़ की 48 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और खजनी विधानसभा के लिए 67 करोड़ की 10 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास शामिल है.

# मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल से बदल रही गौशाला की तस्वीर, वैज्ञानिकों की मदद से नस्ल सुधार पर काम

**बेसहारा गौवंशों ने बदली गौ आश्रय स्थल की तस्वीर, रोल मॉडल बनकर दे रहे आत्मनिर्भरता का अनूठा संदेश**

(जीएनएस)।

मेरठः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल से उत्तर प्रदेश में गौशाला की स्थिति लगातार बदल रही है. रोहटा ब्लॉक के उसकिया का गौशाला आत्मनिर्भरता की नई परिभाषा लिख रहा है. यहां पर नस्ल सुधार के साथ-साथ ईंधन और दुग्धशाला पर भी जोर-शोर से काम हो रहा है.

आत्मनिर्भर और स्वावलंबी गौशालाः जंगलों के बीच बने उसकिया गौशाला में गायों की देखभाल वैज्ञानिक तरीके से की जा रही है. नस्ल सुधार के लिए गौशाला प्रबंधन CIRC के वैज्ञानिकों की मदद ले रहा है. नस्ल सुधार से इन गौ आश्रय स्थलों को गौशाला से दुग्धशाला में परिवर्तन करने के लिए कोशिश हो रही हैं. एक वैज्ञानिकों की टीम भी यहां के लिए अलॉट हो गई है. अब ऐसे पशुओं को चिह्नित करके, उनके मेडिकल परीक्षण कराकर जांच कराते हैं, और फिर अच्छी नस्ल से आगे उनके गर्भधारण हो, इसको लेकर भी प्रयास हो रहे हैं. क्योंकि दो महीने बाद गर्भधारण का सीजन है, तो ऐसे में उससे पहले इन्हें प्रॉपर एक्स्ट्रा डाइट दी जा रही है. मेरठ के मुख्य पशु चिकित्सा चिकित्सा अधिकारी पवित्र जीत सिंह बताते हैं कि, इस गौशाला में लगभग 350 से ज्यादा गोवंश हैं, और यह जंगल के

बीच स्थित गौशाला है. जहां पहले तारबंदी की हुई थी, लेकिन धीरे-धीरे अब यहां जन सहयोग से जन सहभागिता के माध्यम से बाउंड्री भी की जा रही है.

'मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सभी उच्च अधिकारियों की मंशा है कि गौशालाएं आत्मनिर्भर और स्वावलंबी होनी चाहिए. जिसमें मेरठ की कुकरिया में स्थित इस गौशाला को विकसित करने का संकल्प लिया गया, और कुछ ही महीना में यहां बड़ी तब्दीली अब तक हो गई है'.

पवित्र जीत सिंह, मुख्य पशु चिकित्सा चिकित्सा अधिकारी, मेरठ

ऊर्जा के क्षेत्र बड़ी पहलः जंगल में होने के बावजूद इस गौशाला में बिजली और पानी की समस्या नहीं है. ईंधन के क्षेत्र में भी गौशाला खुद पर निर्भर है.गौवंश की वजह से बिजली आपूर्ति बाधित होने का विकल्प भी तैयार कर लिया गया है. बायोगैस प्लांट की मदद से जनरेटर चलता है और उसी से रात को बैटरे भी चार्ज हो जाते हैं. 60 क्यूबिक मीटर क्षमता का बायोगैस प्लांट यहां लगाया गया है. इस प्लांट से गौ आश्रय स्थल में जहां गोवंशों के लिए पानी का इंतजाम, रात को बिजली का इंतजाम, और गर्मी सीजन में बचाव के लिए खास स्प्रिंकलर नियमित चलते हैं. जिससे कि गर्मी के सीजन में यहां गौवंशों को गर्मी से राहत मिल सके. इसी के साथ साथ यहां रहने वाले स्टाफ को भी भोजन के लिए अतिरिक्त ईंधन की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती. क्योंकि यहां लगे बायो गैस प्लांट से गौ आश्रय स्थल में सेवा मे रहने वाले कर्मचारियों के लिए भोजन- चाय बनाने के लिए गैस की व्यवस्था हो जाती है.

'यहां उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, जंगल में रहते हैं, लेकिन बिजली पानी की कोई किल्लत ही नहीं है, ईंधन के लिए कभी शहर की तरफ नहीं जाना पड़ता, सारे इंतजाम यहीं गौवंश की होने की वजह से हो जाते हैं. बिजली कब आई कब नहीं, इस बात की भी कोई टेंशन नहीं है'

राजू, गौशाला के केयरटेकर

गौशाला में चक्की की व्यवस्थाः गौशाला में एक रहट लगाई गई है, जो कि बैलों के बल से आधारित चक्की है. जिससे गौशाला में पशुओं की देखभाल के लिए रहने वाले सदस्यों के लिए आटा चक्की पर नहीं जाना पड़ता, धीरे धीरे इसे और व्यापक स्तर पर लाया जा रहा है, जिससे कि भविष्य में यहां लोग कोल्ड प्रेस आटा तैयार करा सकें.

# सेशेल्स की राजकीय यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी, भारत के लिए क्यों इतना खास है यह द्वीप देश?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून 2026 में सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राजकीय यात्रा करेंगे।.

(जीएनएस)।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून 2026 को सेशेल्स की राजकीय यात्रा करेंगे। सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर यह यात्रा सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस की स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में होगी।

प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार हिंद महासागर के इस छोटे मगर महत्वपूर्ण द्वीप देश के दौरे पर जा रहे हैं। वह वर्ष 2015 में भी सेशेल्स गए थे। इस दौरान भारतीय रक्षा बलों की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के दो जहाज समारोह में भाग लेंगे।

भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व और अफ्रीका से आयात करता है। ये आयात मुख्य रूप से हिंद महासागर के समुद्री मार्गों से होते हैं।

सेशेल्स इन मार्गों के पास स्थित

है, जिससे यह क्षेत्र भारत के लिए महत्वपूर्ण निगरानी और सुरक्षा का केंद्र बन जाता है। साथ ही सेशेल्स को अपने प्रभाव में लाने की कोशिशें चीन भी लगातार कर रहा है।

हिंद महासागर क्षेत्र (आइओआर) में चीन अपनी आर्थिक और रणनीतिक पहुंच बढ़ा रहा है। सेशेल्स जैसे द्वीपीय देशों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, कूटनीतिक संबंधों और संभावित सैन्य सहयोग के जरिए बीजिंग अपनी उपस्थिति मजबूत करना चाहता है।

भारत इस प्रतिस्पर्धा के बीच अपने सहयोग को और गहरा करने पर जोर दे रहा है। सेशेल्स के साथ भारत के संबंध ऐतिहासिक और गहरे हैं। दोनों देश समुद्री सुरक्षा, हाइड्रोग्राफी, रक्षा क्षमता निर्माण और आर्थिक सहयोग के क्षेत्रों में साथ काम कर रहे हैं।

फरवरी 2026 में सेशेल्स के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान सतत विकास, आर्थिक वृद्धि और सुरक्षा पर सहयोग बढ़ाने को लेकर एक दृष्टि प्रपत्र भी जारी किय गया था।

पीएम मोदी की इस यात्रा में राष्ट्रपति हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे। भारतीय नौसेना की भागीदारी समुद्री सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करेगी।

हिंद महासागर क्षेत्र में भारत खुद को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में देखता है। सेशेल्स जैसी जगहों पर मजबूत साझेदारी से भारत समुद्री मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करना चाहता है।

विदेश मंत्रालय की आधिकारिक घोषणा के अनुसार, यात्रा के दौरान दोनों पक्ष द्विपक्षीय संबंधों के पूरे स्पेक्ट्रम की समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय-वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे।